

सम्पादकीय

लेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्री कोर्ट का फैसला अहम, पार्टियों का खर्च निरंकुश

**इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम
कोर्ट का फैसला अहम,
पार्टियों का खर्च निरंकुश**

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी हो, लेकिन चुनाव सुधार के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में शायद भारत अकेला देश है, जहां चुनावी चंदे की कोई सीमा तय नहीं है और पार्टी के खर्च पर भी किसी भी रोक नहीं है।

तरह का काइ राक-टाक नहा हा। चंदे और खर्च की हृदबंदी किए बिना चुनावों में नोटबंदी की कल्पना नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी हो, लेकिन चुनाव सुधार के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सवाल उठता है कि क्या हम अमेरिका और यूरोप के देशों से सीख नहीं ले सकते हैं ब्रिटेन में कोई भी दल चुनाव में एक सीट पर तीस हजार पाउंड (करीब तीस लाख रुपये) से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। इसी तरह, वहां कोई दानदाता (व्यक्ति हो या कंपनी) एक साल में साढ़े सात हजार पाउंड से ज्यादा का दान नहीं दे सकता। उससे ज्यादा दान देने पर उसकी पहचान को सर्वजनिक किया जाना जरूरी है। जर्मनी में अधिकतम चुनावी चंदे की सीमा दस हजार यूरो सालाना है। उससे ज्यादा चंदा देने पर पार्टी विशेष को पहचान से चुनाव करवाए क्राउड फाइंडिंग की तर्ज पर भारत के लोग या कंपनियां चुनाव फंड में योगदान करें। इससे जितना पैसा जमा हो, उतनी ही रकम भारत सरकार को अपनी झोली से दे। फिर यह पैसा अलग-अलग दलों में बांटा जाए। पैसे का आवंटन पिछले लोकसभा चुनावों में मिले गोट और सीटों, उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों तथा गोटरों की संख्या केआधार पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जा सकती है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि चंदा देने वाला आम वोटर भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा। उससे लोगों कि सारी प्रक्रिया में वहां खुद शामिल है और उसकी जेब का पैसा लगा है। इससे चुनाव में स्वच्छ छिप के लोग सामने आयेंगे, और नई पीढ़ी को मौका मिलेगा।



उत्तरांगर नहीं किए जाते, लेकिन बड़े दानदाताओं की पहचान जरूरी है। कहा जाता है कि एक राजनेता कालेधन के जरिये ही विधानसभा या लोकसभा पहुंचता है। इस समय हमारे देश में एक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 75 से 90 लाख रुपये और विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपये खर्च कर सकता है। वैसे तो कागजों में उम्मीदवार इससे आधी रकम ही चुनावी खर्च के रूप में दिखाते हैं, लेकिन हकीकत बच्चा-बच्चा जानता है। ऐसे में, चुनाव आयोग को चुनावी खर्च सीमा बढ़ानी चाहिए और उसे महंगाई दर से भी जोड़ा जाना देशों में यह प्रयोग सफलतापूर्क चल रहा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी का सुझाव है कि राष्ट्रीय चुनाव कोष बनाया जा सकता है, जिसमें कॉरपोरेट जगत चंदा देसकता है। फिर यह पैसा चुनाव आयोग अलग-अलग दलों के बीच बांट सकता है। वैसे बड़े उद्योगपतियों ने पहले ही कॉरपोरेट फंड बना रखा है, जिसके जरिये अलग-अलग दलों को चंदा दिया जाता रहा है। पिछले साल ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया कि भारी-भरकम चंदा देने वालों का सत्तारुद्धरण दलों से जुड़ाव होता है और उन्हें मनचाहे लाभ मिलते हैं।

बनाने का अवस्य नए होने की वजह से आमतौर पर सस्ते होते हैं न्यू फंड ऑफिसेट मैनेजमेंट कंपनी जब नई पंजी को एमसी इक्विटी मार्केट

यूचुअल फंड स्कीम लाती है, तो एसक लिए एनएफओ पेश करती है। इसके जरिये जुटाई पूँजी को एमसी इविटी मार्केट, बॉन्ड या केसी और एसेट में निवेश करती है। इसलिए, एनएफओ पर बाजार में उतार-चढ़ाव का असर रहता है जोगेर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच अगर जोखिम के साथ गुरुआत में ही रिटर्न पाना चाहते हैं तो न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) में निवेश कर सकते हैं। प्रारंभिक वार्जनिक निर्गम (आईपीओ) की वर्ज पर म्यूचुअल फंड चलाने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (एमसी) भी बाजार से पैसा जुटाने के लिए एनएफओ लाती हैं। बाजार में नया



नस्ते हैं। इसके जरिये कंपनियां निवेशकों को अपनी किसी नई स्कीम में लाने के लिए आमंत्रित करती हैं। ऐसे टैनेजरमेट कंपनी नब नई म्यूचुअल फंड स्कीम लाती हैं, तो उसके लिए एनएफओ पेश का फैसला वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम क्षमता और निवेश रणनीति दें अनुरूप होना चाहिए। इसलिए निवेश से पहले गहन रिसर्च करें फंड ऐनेजर की विशेषज्ञता का मूल्यांकन करें। -अखिल चतुर्वेदी मुख्य कारोबार अधिकारी, मोर्टेलाल

आंकड़ों को दिशासूचक की तरह लेने की जरूरत, अब भी सामने खड़ी हैं चुनौतियां

विभिन्न सर्वे बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चमत्कारिक ढंग से आगे बढ़ रही है, जो अच्छी बात भी है। लेकिन आंकड़ों को दिशासूचक की तरह लेने की जरूरत है, क्योंकि सामने खड़ी चुनौतियां उन वास्तविकताओं की तरह हैं, जिन्हें हम नजर अंदाज नहीं कर सकते। विभिन्न सर्वे बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चमत्कारिक ढंग से आगे बढ़ रही है, जो अच्छी बात भी है। लेकिन आंकड़ों को दिशासूचक की तरह लेने की जरूरत है, क्योंकि सामने खड़ी चुनौतियां उन वास्तविकताओं की तरह हैं, जिन्हें हम नजर अंदाज नहीं कर सकते। विभिन्न सर्वे बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पांच जनवरी को पूर्वनुमानित 7.3 फीसदी नहीं, बल्कि 7.6 फीसदी की दर से विकास करेगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन ने सबको हैरान कर दिया। दिसंबर, 2023 तक रिजर्ज बैंक के पेशेवर पूर्वनुमान सर्वे ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी 6.0-6.9 फीसदी के दायरे में रहने की उच्चतम संभावना जताई थी। विकास दर में

नव्विसडी पर कम खर्च और करों में बद्धि के रूप में विश्लेषित किया जाता है। जीवीए में करों को जोड़कर और स्पेंसर से सब्सिडी घटाने पर जीडीपी का आंकड़ा निकाला जाता है। देलचस्प बात यह है कि तीन तेमाहियों में जीवीए क्रमिक रूप से 3.2 फीसदी से घटकर 6.5 फीसदी गया गया है। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर बहसें अक्सर आंकड़ों की गारीकियों में खो जाती है। स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था ने उमीद से न्यादा और पूर्वनुमानों से बेहतर दर्दशन किया है। यह बुनियादी जीडीपी वृद्धि दर छह फीसदी के आस-पास होगी। सामाजिक व्यवस्था के अन्य तत्वों की तरह आर्थिक विकास भी औसत के नियम से नियंत्रित होता है। क्या यह गिरावट है, सार्विकीय प्रभाव है या कोई संरचनात्मक मुद्दा है, जिसे विकास को बनाए रखने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए? आंकड़े बताते हैं कि विकास की इस गति में हर क्षेत्र शामिल नहीं है। भले ही जीडीपी 7.6 फीसदी की दर से विकास कर रहा हो, पर तथ्य यह है कि निजी खपत मुश्किल से तीन ज्यादा लोगों को ग्रामीण रोजगार के अलावा धन हस्तांतरण, घर एवं उपभोग्य सामग्रियों के प्रावधान जैसे कल्याणिकारी कार्यक्रमों के आक्रामक विस्तार के बावजूद खपत घट रही है। इसका असर कम लागत वाली वस्तुओं की बिक्री एवं उपभोक्ता वस्तुओं तथा टिकाऊ निर्माताओं की कमाई पर दिख रहा है। दरअसल, अंतरिम बजट के पहले उद्योग मंडलों ने कल्याणिकारी लाभों के विस्तार की बात की थी। जीडीपी के अनुमानों में अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। देश की जनसांख्यिकी से पता चलता है कि युवा कार्यबल अब ज्यादातर उत्तर के सबसे आबादी वाले राज्यों में रहते हैं, जबकि विकास, रोजगार, आय और खपत का झुकाव भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों की ओर है। 60 हजार नौकरियों के लिए 48 लाख युवा आवेदन देते हैं, राज्यों में अक्सर पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट कॉलेजों में कैंपस लेसर्स में भारी गिरावट आई है। इन सबके पारे दूसरा प्रलयांक और सांघर्षात्मक



खड़ा चुनावतया उन वास्तवकताओं की तरह हैं, जिन्हें हम नजर अंदाज नहीं कर सकते। एक पुरानी कहावत है कि आमतौर पर लोग उस बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, जिसे वे सच मानना चाहते हैं। हरेक कुछ महीनों में भारत की सार्वजनिक बहस में यही सच सामने आता है। अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में आंकड़े सामने आते ही बयानबाजी शुरू हो जाती है। बेहद ध्वीकृत राजनीतिक अखाड़े में समर्थक वाह-वाह करते हुए और शक्की अविश्वास में बहस यह गृह्य पछल वर्ष आर तिमाहीया के आंकड़ों में संशोधन के बाद हुई है, जिसके तहत वर्ष 2022-23 की जीडीपी विकास दर कम रही और मौजूदा वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों में यह ऊपर दिखी। इसमें यह खुलासा भी किया गया कि अक्टूबर और दिसंबर, 2023 के बीच अर्थव्यवस्था 8.4 फीसदी की दर से बढ़ी। जीडीपी की 8.4 फीसदी दर पर बहुत ज्यादा उत्साह पैदा हुआ, जबकि इस अवधि के लिए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 6.5 फीसदी था। कम जीवीए को

परंचनाओं पर खंच आर जाएस्टा वरं प्रत्यक्ष करों के आंकड़ों से भी यह प्रमाणित होता है। जीडीपी के अनुमान में विनिर्माण एवं निर्माण के क्षेत्र में भी मजबूत वृद्धि का पता चलता है। आय में वृद्धि और शेयर मौद्यकांकों की शानदार उछाल से इसकी पुष्टि होती है। यह सब चीकारत हुए भी कहना होगा कि नब कुछ ठीक नहीं है। ये अनुमान वेकास की रफ्तार और गति में अंदी का भी संकेत देते हैं। वर्ष के अंत में 7.6 फीसदी का अनुमान बताता है कि चौथी तिमाही में फिसदी का दर से बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय होना चाहिए। खपत के आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि जीडीपी में खपत का योगदान 55.6 फीसदी होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि खपत में गिरावट एक मौसमी मुद्दा है या खर्च करने की क्षमता में बुनियादी गिरावट है। हालांकि पौँडा को कम करने और खपत बढ़ाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप किया गया है। लेकिन 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवा, 16 करोड़ से बढ़ रहा है लोकतंत्र का विचार, 'रामराज्य' में चिताजनक आंकड़े भारत के दो सबसे बड़े नियोक्ताओं से संबंधित हैं। पहला सेवा क्षेत्र, जो बड़ी संख्या में नए रोजगार पैदा करता है और दूसरा कृषि, जो संपूर्ण कार्यबल के 45 फीसदी से ज्यादा कार्यबल को रोजगार देती है। कृषि में तीसरी तिमाही में संकुचन दिखाई दिया और वर्ष के अंत में उसकी वृद्धि दर 0.7 फीसदी हो सकती है। सेवा क्षेत्र भी पिछले गया है और दोहरे अंक की वृद्धि के ऐतिहासिक स्तर से काफी नीचे रुका हुआ है। कुछ अन्य है। आर्थिक विकास एवं नीति के लिए संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो हम जानते हैं और जो हम जानते हुए भी आंख मूँद कर बैठे हैं, के बीच झूल रही है। आंकड़ों को दिशासूचक की तरह लिया जाना चाहिए। आर्थिक विकास की गति, चुनौतियां, बाधाएं इत्यादि सब पर बहस होनी चाहिए। याद रखें, चुनौतियों का दबाव जितना ज्यादा होगा, अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उतना ही निखरता जाएगा।

नया 'परिवार नियोजन'
हर व्यक्ति अपनी एक छोटी पार्टी बनाता है और उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ दर्शाये जाता है। विधायक, पार्षद और पंच तक ले जाएं तो हर कोई अपने क्षेत्राधिकाराएं संग प्रति 'परिवार' के 'प्रेसिडा'

कपना का तरह लगता हा उसका नियंता वह स्वयं और बाद में उसकी संताने इसका चार्ज ले लेती हैं। मतदाता के पास इतना ही विकल्प रहता है कि वह इस परिवार को चुने या उस परिवार को। महा उपनिषद् में हमारे ऋषियों ने जिस उदात्त और वैश्विक भाव से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की उक्ति कही होगी, तब उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि हजारों साल बाद भारत में इस कौटुम्बिक भाव का रूपांतरण राजनीतिक परिवारवाद में हो जाएगा। परिवार सत्ता पर कबिज होने और उसे कायम रखने तथा ऐसा करने वाले राजनीतिक निशाने पर होंगे। जाहिर है एक समय ऐसा भी आएगा कि सत्ता का संघर्ष परिवारवाद और गैरपरिवारवाद के बीच केन्द्रित होने में एक पांचाल का पापण का बोझ लिए चल रहा है, क्योंकि इसी परिवार में वोट के बीजाणु छिपे हुए हैं। अर्थात् यह नया परिवारवाद असल में वोटवाद का परिवारीकरण है। गुजरे समय में राजपरिवारों में सत्ता संघर्ष हुआ करता था। राजा का बेटा ही राजा बनता था। मुगलों के जमाने में तख्त के लिए एक बेटा अपने ही सगे भाइयों को मौत के घाट उतारने में नहीं हिचकता था। बाद में अंग्रेज आए तो सत्ता संचालन का नया कंसेप्ट लेकर आए, जो मूलतः वशंवादी होते हुए भी उपनिवेशों में शेशवर लोगों के भरोसे ज्यादा था। आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र कायम हुआ तो सामंती परिवारवाद ने भी नया चौला पहन लिया। कुछ राजपरिवारों ने



तलवार और ढाल दोनों बनाने में कामयाब होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सत्ता के खोल में लिपटा नया परिवार नियोजन है, जिसमें परिवार की हड्डें और स्वार्थ राजनेता अपने अपने हिसाब और सुविधा से तय कर रहे हैं। हाल में बिहार की राजधानी पटना में आयोजित इंडिया गठबंधन की महारौली ने लालपूरसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परिवार पर सवाल उठाए तो जवाब में मोदी ने कहा कि सारा देश ही उनका परिवार है। या यूं कहें कि मोदी ही देश हैं और देश ही उनका परिवार है। इसी तर्ज पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश वुडमार, जिन्होंने राजनीतिक पलटीमारी में नए मानदंड कायम किए हैं, ने कहा कि सारा बिहार ही मेरा परिवार

नैतिक मूल्यों के साथ सामुदायिक कल्याण पर जोर

। लोकन नातक मूल्या का भावश्यकता का केंद्र 'रामराज्य' में भी मिलता है। चुनाव की धुकड़-धुकड़ से सज्जाटा-सा छाया है! 'लोकतंत्र पर्व' की दाल केवल चुनावी भट्टी में ही गलती है! कृषि-प्रधानता छोड़, रश चुनाव-प्रधान हो गया है, इसलिए बारहों महीने रात-दिन सस्फुगत का सच्चा आत्मा का प्रतिष्ठित करता है तथा एक समरस और आदर्श शासन व्यवस्था प्रदान करता है। लोकतंत्र से जुड़े खतरों की गहरी पड़ताल करें, तो भारतीय संर्दभ में रामराज्य एक उपयुक्त और सार्थक विकल्प के रूप में हमारे लोकतंत्र की कोख में पलते हैं। लोकतंत्र सामने प्रस्तुत होता है।



श किसी भी अभाव में चल सकता है, लोकतंत्र के बिना नहीं! मगर अवतंत्रता के बाद देश के भीतर वेवादों और अलगाववाद के किले बढ़े करते-करते लोकतंत्र स्वयं छड़खड़ाने लगा है और अपना जीवंत वेकल्प मांगने लगा है। संयोग है कि इसी बीच राष्ट्रीय परिषद की ओर भी भाजपा ने अयोध्या के राम मंदिर को देश के लिए 'ऐतिहासिक और अनुपम उपलब्धि' बताते हुए एक कालचक्र के श्रीगणेश के साथ भारत में अगले एक हजार वर्षों के लिए रामराज्य की स्थापना का एक नंकल्प पारित किया है। भारत की समृद्धि से भरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धारा में शासन प्रबंधन के दो मॉडल प्रकट होते हैं : लोकतंत्र और रामराज्य। लोकतंत्र को राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक है, जिसे आदर्श शासन व्यवस्था माना जाता है और सेंद्रियिक रूप से यह आदर्श व्यवस्था है भी। लेकिन समय का पहिया धूमता है और किसी व्यवस्था में बाह्य तत्वों का शानैः शानैः अतिक्रमण उसे निर्मूल कर देता है। यही लोकतंत्र के साथ भी हुआ है और निरंतर हो रहा है। स्वयं को लोकतंत्र का संरक्षक मानने वाले पश्चिमी और यूरोपीय देशों के लोकतंत्र में गैर-लोकतांत्रिक तत्वों का प्रदूषण इस हड तक फैल चुका है कि वह दिन दूर नहीं, जब इन देशों के मूल नागरिक इस पर पछाटाएंगे। भारत में लोकतंत्र-प्रदत्त स्वच्छंदंता से भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन की प्रक्रियाओं को ऑक्सीजन देने के सब पर्यायवाची-से बन गए हैं। लोकतंत्र अब कोई पवित्र गाय नहीं रह गया है, जिसे प्यार से पाला-पोसा जाए और जिस पर गर्व किया जाए। इसके स्थान पर हम उस आदर्श शासन प्रणाली की ओर लौटें, जो सदियों से भारतीय मानस की रग-रग में जिंदा है और जिसकी कल्पना मात्र से ही हमारा रोम-रोम सोमांचित हो उठता है, जिसे हम रामराज्य कहते हैं। रामराज्य का अवतरण प्राचीन हिंदू शास्त्रों में होता है, विशेषकर रामायण में, जहां भगवान राम को न्यायपूर्ण और दयालु शासक के रूप में दिखाया जाता है, जिनके राज्य में सभी एक ही संस्कृति की छाया में रहते हैं, सब बराबर हैं, सब सुखी हैं, सब संपन्न, संतुष्ट और के कल्याण के प्रति दायित्व और समर्पण की भावना के आधार पर मार्गदर्शित होते हैं। शासन के जटिल परिदृश्य का सामना करते हुए, भारत स्वयं को जनतंत्र और रामराज्य के बादों और चुनौतियों के बीच फंसा पाता है। रामराज्य, जिसमें सामंजस्य, नैतिक नेतृत्व और सामुदायिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित है, एक प्रेरणादायक विकल्प के रूप में प्रकट होता है, जो भारतीय सभ्यता के मूल्यों का समर्थन करता है। जनतंत्रीय तत्वों और रामराज्य में समाहित शासन-गुणों के बीच संतुलन स्थापित करने से भारत जैसे विविध संस्कृति-संपन्न राष्ट्र के सामने आई विशेष चुनौतियों का सामना करने का मार्ग खल

